



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

27 भाद्र 1939 (श10)  
(सं0 पटना 846) पटना, सोमवार, 18 सितम्बर 2017

---

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

14 सितम्बर 2017

सं0 ग्रा0वि0-7(आं.)-51/2013-328228—महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) की धारा 32 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-

**महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार -  
विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।—**

- (1) यह नियमावली “महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना बिहार- विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017” कही जा सकेगी ।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
- (3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी ।

**2. परिभाषाएं ।—**इस नियमावली में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (i) “अधिनियम” से अभिप्रेत है, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित);
- (ii) “राज्य सरकार” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार, बिहार;
- (iii) “धारा” से अभिप्रेत है, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा (समय-समय पर यथा संशोधित);
- (iv) “मजदूरी दर” से अभिप्रेत है, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के

अकुशल श्रमिकों के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर अथवा राज्य सरकार या ग्रामीण विकास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित मजदूरी की दर;

- (v) "कार्यक्रम पदाधिकारी" से अभिप्रेत है प्रखण्ड का कार्यक्रम पदाधिकारी / प्रभारी कार्यक्रम पदाधिकारी;
- (vi) "MIS" से अभिप्रेत है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित ऑनलाइन "प्रबंधन सूचना प्रणाली" यथा- [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) ;
- (vii) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्द एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों या मास्टर सर्कुलर में परिभाषित किये गये हों ।

**3. उद्देश्य ।**—महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, बिहार – विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान नियमावली, 2017 का उद्देश्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मजदूरी प्राप्तकर्ता को ससमय भुगतान एवं उत्तरदायी तंत्र को सुनिश्चित करना है ।

#### 4. क्षतिपूर्ति ।—

- (1) अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार, कामगार साप्ताहिक ष थार पर मजदूरी भुगतान पाने और किसी भी परिस्थिति में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख के पंद्रह दिनों के अंदर भुगतान पाने के हकदार हैं। यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर मजदूरी भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-II के पारा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन से विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए हकदार है ।
- (2) मजदूरी प्राप्तकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान, विलम्ब के लिए उत्तरदायी पाये गये सम्बंधित पदाधिकारियों / कर्मियों को विधिवत दण्डित करते हुए इस प्रकार से की जायेगी कि जुर्माने की राशि देय क्षतिपूर्ति के बराबर हो ।
- (3) जिस तिथि को क्षतिपूर्ति भुगतेय है उस तिथि से पंद्रह दिनों के पश्चात् क्षतिपूर्ति के भुगतान में कोई विलम्ब मजदूरी के भुगतान में विलम्ब के समान ही विचारणीय होगा। कार्यक्रम पदाधिकारी विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संबंध में इसके भुगतेय तिथि के 15 दिनों के भीतर निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी होंगे । इसमें विफल रहने पर उक्त विलम्ब के लिए क्षतिपूर्ति की वसूली कार्यक्रम पदाधिकारी से की जायेगी ।
- (4) मजदूरी भुगतान में जबाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न पदाधिकारियों / कर्मियों की अभियोज्यता की गणना हेतु उन्हें सौंपे गए गतिविधि को पूरा करने के लिए अनुज्ञेय दिनों की संख्या निम्नलिखित रूप में होगी :-

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	पदाधिकारी / कर्म का नाम / पदनाम	गतिविधि को पूर्ण करने के लिए अनुमत दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में इसे प्रविष्ट करना	पंचायत तकनीकी सहायक (पी0टी0ए0) / समकक्ष	T + 3 days
(2)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जाँच	कनीय अभियंता (जे0ई0) या सहायक अभियंता(ए0ई0) (जैसी स्थिति हो)	T + 4 days

क्र. सं.	गतिविधि का नाम	पदाधिकारी / कर्मि का नाम / पदनाम	गतिविधि को पूर्ण करने के लिए अनुमत दिवस
(1)	(2)	(3)	(4)
(3)	eMB में कार्य की मापी एवं माप पुस्तिका में की गयी प्रविष्टि का सत्यापन एवं जाँच	सहायक अभियंता(ए0ई0) / कार्यपालक अभियंता (ई0ई0) (जैसी स्थिति हो)	<u>T + 6 days</u>
(4)	eMR एवं eMB / MB कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रस्तुत करना	पंचायत रोजगार सेवक (पी0 २0एस0)	<u>T + 7 days</u>
(5)	ई मस्टर रोल एवं eMB को MIS पर अपडेट करना तथा वेज लिस्ट निर्गत करना तथा भुगतान के लिए भेजना	लेखापाल / कंप्यूटर ऑपरेटर / समकक्ष	<u>T + 9 days</u>
(6)	फण्ड ट्रान्सफर ० ईर (FTO) generate करना तथा हस्ताक्षर करना (1 <sup>st</sup> Signatory)	मनरेगा लेखापाल / समकक्ष	<u>T + 10 days</u>
(7)	भुगतान के लिए फण्ड ट्रान्सफर ० ईर (FTO ) स्वीकृत करना (2 <sup>nd</sup> Signatory)	कार्यक्रम पदाधिकारी (PO)	<u>T + 11 days</u>
नोट : "T", से अभिप्रेत है, नोट- "T" अभिप्रेत है, से मस्टर रोल बंद होने की तारीख ।			

- (5) मस्टर रोल के बंद होने की तिथि कुल भुगतान मजदूरी, विलम्ब की अवधि तथा 2<sup>nd</sup> Signatory द्वारा FTO स्वीकृति की तिथि के ० धार पर कुल देय क्षतिपूर्ति की गणना स्वतः नरेगा सॉफ्ट द्वारा की जाएगी । प्रत्येक स्थिति में भुगतान क्षतिपूर्ति स्वतः [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) पर प्रदर्शित की जाएगी एवं प्रतिदिन अद्यतन की जाएगी ।
- (6) क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान यथोचित सत्यापन के उपरान्त किया जाना है । प्रत्येक कार्यक्रम पदाधिकारी विलम्ब क्षतिपूर्ति के देय होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर यह निर्णय लेंगे कि नरेगा सॉफ्ट द्वारा स्वतः गणना की गई क्षतिपूर्ति देय है या नहीं ? क्षतिपूर्ति का भुगतान राज्य रोजगार गारंटी निधि (SEGF) upfront से की जाएगी । इसकी वसूली विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारियों / कर्मियों / एजेंसियों से की जाएगी ।
- (7) अपवाद की स्थिति जब क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं हो सकेगी :-
- (क) भुगतान करने वाले प्राधिकार स्तर पर निधि उपलब्ध न हो ;
- (ख) क्षतिपूर्ति देय न हो ;
- (ग) गृह-मंत्रालय (एमएचए) द्वारा यथा-परिभाषित प्राकृतिक आपदा ।
- (8) कार्यक्रम पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मुआवजे के दावों का निपटारा निर्धारित समय अर्थात् मुआवजा देय होने के 15 दिनों के भीतर हो जाय और इस प्रकार के दावों को बिना किसी स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के संग्रहित / लंबित रखने करने की

अनुमति नहीं होगी। अस्वीकृति वाले सभी मामलों में कार्यक्रम पदाधिकारी अस्वीकृति का विस्तृत कारण नरेगासॉफ्ट पर अपलोड करेंगे और भविष्य में सत्यापन के लिए अपने कार्यालय में इसका रिकार्ड संधारित करेंगे। मुआवजे के भुगतान के लिए स्वीकृत सभी मामले इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ई-एफओएमएस) के माध्यम से होंगे। जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक नियमित रूप से हर माह इसकी समीक्षा करेंगे।

- (9) राज्य सरकार (जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक और विशिष्ट रूप से कार्यक्रम पदाधिकारी) विलम्ब से मजदूरी भुगतान के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसका ब्यौरा नरेगासॉफ्ट पर अपलोड किया जाना है ताकि देर से किए गए भुगतान के मामले में प्रत्येक पदाधिकारी / कर्मी / एजेंसी की जवाबदेही विनिश्चित की जा सके। उक्त क्षतिपूर्ति की वसूली संबंधित पदाधिकारी / पदाधिकारियों / कर्मी / कर्मियों से किया जाना है तथा कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इसका आदेश निर्गत किया जायेगा।
- (10) **भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति की राशि का लेखांकन।-** भुगतान किये गये क्षतिपूर्ति के लेखांकन के लिए एस0ई0जी0एफ0 के अंतर्गत एक अलग से खाता संधारित की जाएगी तथा ई-एफओएमएस0 के अंतर्गत एम00 ई0एस0 पर प्रदर्शित की जाएगी। जिला कार्यक्रम समन्वयक, अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक और कार्यक्रम पदाधिकारी अकुशल मजदूरी के भुगतान में उक्त विलम्ब के लिए भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की राशि की वसूली पदाधिकारी / पदाधिकारियों / कर्मी / कर्मियों के मानदेय / वेतन से करना सुनिश्चित करेंगे। वसूल की गयी उक्त राशि की प्रतिपूर्ति एस0ई0जी0एफ0 लेखा में की जाएगी।

**5. शंकाओं का निराकरण।-** यदि इस नियमावली के किसी उपबंध की व्याख्या के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, तो उस मामले को ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार को अग्रसारित किया जायेगा और उसका निर्णय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

**बिहार-राज्यपाल के आदेश से**

(ह0) अस्पष्ट,

सरकार के सचिव।

The 14<sup>th</sup> September 2017

No. ग्रा0वि0-7(आं.)-51/2013-328228—In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 32 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Act No. 42 of 2005), the state government hereby makes the following rules:—

**Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Bihar Compensation to workers for the delay in Wage Payment Rules, 2017**

**1. Short title, extent and commencement.-**

- (1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Bihar – Compensation to workers for the delay in Wage Payment Rules, 2017.
- (2) It shall extend to whole State of Bihar.

- (3) It shall come into force from date of its publication in the official Gazette.

**2. Definitions.**—In the rule, unless required otherwise the context-

- (i) “Act”, means Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005( As amended from time to time);
- (ii) “State Government”, means State Government of Bihar;
- (iii) “Section”, means section of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (as amended from time to time) ;
- (iv) “Wage Rate”, means the wage rate notified by the Government of India in exercise of power conferred under section 6(1) of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 for unskilled labour for the State of Bihar or wage rate notified by state government or Rural Development Department, Bihar;
- (v) “Programme Officer”, means the Programme Officer/ In charge Programme Officer of the Block;
- (vi) “MIS”, stands for the online Management Information System established and managed by Ministry of Rural Development, Government of India, i.e., [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) ;
- (vii) Words and expressions used and not defined in these rules, shall have the same meaning as defined in the Act or in Guidelines or Master circular issued by the Central or State Government from time to time.

**3. Objective.**—The objective of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, Bihar - Compensation to workers for the delay in Wage Payment Rules, 2017 is to ensure timely payment to wage seekers and accountable mechanism for effective implementation of the Act.

**4. Compensation.**—

- (1) According to section 3(3) of The Act, workers are entitled to be paid wage on a weekly basis and in any case within a fortnight of the date of closure of the muster roll. In case the payment of wages is not made within fifteen days from the date of closure of the muster roll, the wage seeker, as per Para 29 of Schedule II of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, is entitled to receive payment of compensation for the delay, at the rate of 0.05% of the unpaid wages per day of delay from sixteenth day of closure of muster roll.
- (2) The compensation to the wage seekers will be paid duly penalizing the functionaries found responsible for the delay in such a way that the penalty is equal to the compensation payable.
- (3) Any delay in payment of compensation beyond a period of fifteen days from the date it becomes payable, shall be considered in the same manner as the delay in payment of wages. The Programme Officer will be responsible for taking a decision regarding acceptance or rejection of the delay compensation within fifteen days from the date it becomes payable. In Case of failure, the compensation for such delay shall be recovered from the Programme Officer.

- (4) For ensuring the accountability in payment of wages and to calculate culpability of various functionaries, the number of days permissible to accomplish the activity assigned to them, will be as follows :-

Sl. No.	Name of the Activity	Name/Designation of the functionary	Permissible No. of days to Complete the Activity
(3)	(4)	(3)	(4)
1.	Measurement of Work in eMB and recording it in the Measurement Book	Panchayat Technical Assistant (PTA)/equivalent	<u>T + 3 days</u>
2.	Verification and Checking of Measurement of Work in eMB and recording it in the Measurement Book	Junior Engineer(JE) or Assistant Engineer(AE) (as the case may be)	<u>T + 4 days</u>
3.	Verification and Checking of Measurement of Work in eMB and recording it in the Measurement Book	Assistant Engineer (AE)/Executive Engineer(EE) (as the case may be)	<u>T+6 days</u>
4.	Submission of eMR and eMB / MB to Programme Officer.	Panchayat Rozgar Sewak ( PRS)	<u>T + 7 days</u>
5.	Updation of eMR and eMB on MIS and generation of wage list and sending it for Payment	Accountant/Computer Operator / Equivalent	<u>T + 9 days</u>
6.	Generation of Fund Transfer Order (FTO) and Signing ( 1 <sup>st</sup> Signatory )	MGNREGA Accountant / Equivalent	<u>T + 10 days</u>
7.	Approval of Fund Transfer Order(FTO) for payment (2 <sup>nd</sup> Signatory)	Programme Officer(PO)	<u>T + 11 days</u>
Note: "T ", means Date of Closure of Muster Rolls			

- (5) The total compensation payable shall be automatically calculated by NREGA Soft based on the date of closure of muster roll, total wage payable, duration of delay and the date of approval of FTO by 2<sup>nd</sup> Signatory. The compensation payable in each case will be displayed automatically on [www.nrega.nic.in](http://www.nrega.nic.in) and updated daily.
- (6) The compensation is to be paid after due verification. Every Programme Officer shall, within 15 days from the date that the delay compensation becomes due, decide whether the compensation that has been automatically calculated by the NREGA Soft is payable or not? The Compensation shall be met from the State Employment Guarantee Fund (SEGF) upfront. This will be recovered from the functionaries/agencies responsible for the delay.
- (7) Exceptional cases when compensation may not be payable:-
- Funds are not available at the paying authority level;
  - Compensation is not due;
  - Natural calamities as defined by the Ministry of Home Affairs (MHA).
- (8) The Programme Officer will ensure that compensation claims are settled during the prescribed time, i.e., within 15 days of compensation being due, and such claims will not be allowed to be accumulated without any decision of acceptance or rejection. In all cases of rejection, the Programme Officer shall give detailed reason(s) for rejection on NREGA Soft and maintain record of the same, in her/his office for future verification. All cases approved for payment

of compensation shall be routed through Electronic Fund Management System (e-FMS). District Programme Coordinator and Additional District Programme Coordinator will review this every month regularly.

- (9) The State Government (District Programme Coordinator, Additional District Programme Coordinator and Programme Officer in particular) shall be responsible for operationalising the system for the payment of compensation for delayed wage payments. The details are to be uploaded on NREGA Soft so that the liability of each functionary/agency can be determined in case of a delayed payment. The said compensation has to be recovered from the concerned functionary/ functionaries and order for the same shall be issued by the Programme Officer.
- (10) **Accounting for Compensation paid.-** For Accounting for the compensation paid, a separate account within SEGF shall be maintained and reflected in the MIS under e-FMS. The District Programme Coordinator, Additional District Programme Coordinator and Programme Officer shall ensure recovery of compensation amount so paid from the honorarium / salary of the functionaries, for such delay in payment of unskilled wages. The amount so recovered shall be reimbursed into the SEGF account.

**5. Removal of doubts.—** If any doubt arises as to the interpretation of any of the provision of these rules, the matter shall be referred to the Rural Development Department, Government of Bihar, whose decision shall be final after consultation of The Law Department.

**By Order of the Governor of Bihar,**

**Sd/- Illegible,**

*Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण) 846-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>